Samyak
An Institute For Civil Services

Model Answer

Que. Explain the components of revenue receipts and revenue expenditure in the Union Budget. How do they impact fiscal stability in India?

Revenue receipts and revenue expenditure are crucial components of the Union Budget, reflecting the government's financial health. **Revenue receipts** include income earned by the government through taxes and non-tax sources, while **revenue expenditure** refers to spending that does not create assets but is necessary for governance and welfare. Maintaining a balance between these components is essential for fiscal sustainability.

Revenue Receipts: Sources and Components

Revenue receipts are divided into two categories:

A. Tax Revenue (Major Source of Government Income)

- **Direct Taxes**: Income Tax, Corporate Tax
- **Indirect Taxes**: Goods and Services Tax (GST), Customs Duty, Excise Duty
- **Latest Data**: As per the **Union Budget 2023-24**, gross tax revenue is projected at ₹33.61 lakh crore.

B. Non-Tax Revenue

- **Dividends and Profits**: Earnings from Public Sector Undertakings (PSUs), Reserve Bank of India (RBI) surplus transfer.
- **Interest Receipts**: From loans given to states or other entities.
- **Fees and Fines**: Passport fees, spectrum auction revenue, penalties, etc.
- **Grants-in-Aid**: Receipts from foreign institutions or other governments.

Samyak
An Institute For Civil Services

Revenue Expenditure: Nature and Categories

Revenue expenditure refers to recurring expenses required for the functioning of the government. These do not result in asset creation but are essential for governance and welfare.

Major Components of Revenue Expenditure

- **Interest Payments**:
  - The largest component of revenue expenditure.
  - Budget 2023-24 allocated **₹10.8 lakh crore** for interest payments, nearly **40% of revenue receipts**.
- **Subsidies**:
  - **Food Subsidy** (₹1.97 lakh crore) – Allocation for NFSA (National Food Security Act).
  - **Fertilizer Subsidy** (₹1.75 lakh crore) – To aid farmers.
  - **Petroleum Subsidy** – To support LPG and kerosene affordability.
- **Salaries, Pensions, and Administrative Expenses**:
  - Government employee wages and pension commitments.
  - Armed forces and civil pension expenditures.
- **Grants to States & Union Territories**:
  - Financial assistance to states for centrally sponsored schemes.
- **Social Sector Spending**:
  - Health, education, rural employment (e.g., **PM Poshan, MGNREGA**).

Impact on Fiscal Stability

- **Revenue Deficit**: When revenue expenditure exceeds revenue receipts. Budget 2023-24 estimated a **revenue deficit of 2.9% of GDP**.

- **Fiscal Deficit**: Persistent revenue deficits force the government to borrow, increasing the fiscal deficit. The **fiscal deficit target is 5.9% of GDP for 2023-24**.
- **Need for Fiscal Prudence**:
    - **Rationalizing subsidies** to reduce unnecessary expenses.
    - **Expanding the tax base** through better compliance and digitization.
    - **Enhancing non-tax revenue** (e.g., asset monetization).

Conclusion

Revenue receipts and revenue expenditure define the government's fiscal space and policy flexibility. A balanced revenue structure is essential for sustainable economic growth. The government's focus on **tax reforms, expenditure rationalization, and FRBM Act guidelines** ensures fiscal discipline. Reducing revenue deficit while ensuring welfare spending remains a key challenge for policymakers.

प्रश्नः केंद्रीय बजट में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के घटकों की व्याख्या कीजिए। वे भारत में राजकोषीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं?

राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो सरकार की वित्तीय सेहत को दर्शाते हैं। राजस्व प्राप्तियों में करों और गैर-कर स्रोतों के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित आय शामिल होती है, जबकि राजस्व व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है, लेकिन शासन और जन कल्याण के लिए आवश्यक है। राजकोषीय स्थिरता के लिए इन घटकों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

राजस्व प्राप्तियाँ: स्रोत और घटक

राजस्व प्राप्तियाँ दो श्रेणियों में विभाजित हैं:

A. कर राजस्व (सरकारी आय का प्रमुख स्रोत)

1. *प्रत्यक्ष करः आयकर, कॉर्पोरेट कर*
2. *अप्रत्यक्ष करः माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क*
3. *नवीनतम डेटाः केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, सकल कर राजस्व ₹33.61 लाख करोड़ होने का अनुमान है।*

B. गैर-कर राजस्व

1. *लाभांश और लाभः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिशेष हस्तांतरण से आय।*
2. *ब्याज प्राप्तियाँः राज्यों या अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण से।*
3. *शुल्क और जुर्मानाः पासपोर्ट शुल्क, स्पेक्ट्रम नीलामी राजस्व, जुर्माना, आदि।*
4. *अनुदान सहायताः विदेशी संस्थानों या अन्य सरकारों से प्राप्तियाँ।*

राजस्व व्ययः प्रकृति और श्रेणियाँ

राजस्व व्यय से तात्पर्य सरकार के कामकाज के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय से है। इनसे संपत्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि ये शासन और जन कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं।

राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

1. *ब्याज भुगतान:*
    1. *राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक।*
    2. *बजट 2023-24 में ब्याज भुगतान के लिए ₹10.8 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% है।*
2. *सब्सिडी:*
    1. *खाद्य सब्सिडी (₹1.97 लाख करोड़) - NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के लिए आवंटन।*
    2. *उर्वरक सब्सिडी (₹1.75 लाख करोड़) - किसानों की सहायता के लिए।*
    3. *पेट्रोलियम सब्सिडी - LPG और केरोसिन की सामर्थ्य का समर्थन करने के लिए।*
3. *वेतन, पेंशन और प्रशासनिक व्यय:*
    1. *सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन प्रतिबद्धताएँ।*
    2. *सशस्त्र बल और नागरिक पेंशन व्यय।*
4. *राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान:*
    1. *केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता।*
5. *सामाजिक क्षेत्र में खर्च:*
    1. *स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण रोजगार (जैसे, पीएम पोषण, मनरेगा)।*

राजकोषीय स्थिरता पर प्रभाव

- ***राजस्व घाटा:*** *जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। बजट 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% राजस्व घाटा होने का अनुमान है।*
- ***राजकोषीय घाटा:*** *लगातार राजस्व घाटा सरकार को उधार लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है।*
- ***राजकोषीय विवेक की आवश्यकता***
    - *अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना*
    - *बेहतर अनुपालन और डिजिटलीकरण के माध्यम से कर आधार का विस्तार करना*
    - *गैर-कर राजस्व (जैसे, परिसंपत्ति मुद्रीकरण) को बढ़ाना।*

निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय सरकार के राजकोषीय परिदृश्य और नीतिगत लचीलेपन को परिभाषित करते हैं। सतत आर्थिक विकास के लिए एक संतुलित राजस्व संरचना आवश्यक है। कर सुधारों, व्यय युक्तिकरण और FRBM अधिनियम दिशानिर्देशों पर सरकार का ध्यान राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। कल्याणकारी व्यय सुनिश्चित करते हुए राजस्व घाटे को कम करना नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।